

नई पहल : सीधे खाते में होगा भुगतान, बांटने के लिए 39 करोड़ रुपये मंजूर

आधार कार्ड बनवाने पर मिलेंगे सौ रुपये

रमण शुक्ला, पटना

सूबे में आधार कार्ड बनवाने पर गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) वाले सौ रुपये भत्ता पाएंगे। पहले चरण में सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर्मियों को भत्ता भुगतान करने का निर्णय किया है। मनरेगा कर्मियों के आंकड़े जुटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। योजना के तहत 39 करोड़ बांटने की मंजूरी मिली है, हालांकि जरूरत 235 करोड़ रुपये से ज्यादा की है। ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रदीप कुमार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर शेष राशि उपलब्ध कराने की मांग की है।

सरकार के इस पहल से प्रदेश के 8 करोड़ बीपीएल लाभान्वित होंगे।

गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मिलेगा लाभ

- ◆ पहले चरण में मनरेगा कार्ड धारक होंगे लाभान्वित
- ◆ प्रदेश के 8 करोड़ बीपीएल लाभान्वित होंगे

ग्रामीण विकास विभाग शीघ्र ही भुगतान प्रक्रिया शुरू करने की कवायद में जुटा है। भत्ते का भुगतान संबंधित व्यक्ति के खाते में करने की योजना बनी है। पहल को अमलीजामा पहनाने के लिए आधार कार्ड बनवाने वाले मनरेगा बीपीएल के खातों की जानकारी जुटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। दरअसल, मजदूर आधार कार्ड बनवाने में इसलिए भी दिलचस्पी नहीं ले रहे, क्योंकि उसके लिए वक्त देने पर

दिहाड़ी मारे जाने की आशंका है। लिहाजा सरकार ने आधार कार्ड बनवाने के एवज में मजदूरी नुकसान की भरपाई के उद्देश्य से यह पहल की। सरकार ने माना था कि कार्ड बनवाने के दौरान घंटों समय लगने की वजह से मजदूर वर्ग के लोगों को दिहाड़ी का नुकसान होता है। ऐसे में इसकी भरपाई के लिए सरकार ने प्रति बीपीएल को सौ रुपये देने का निर्णय किया था, ताकि आसानी से कार्ड



बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। शुरुआत में विभिन्न कारणों से आधार कार्ड बनाने की योजना उद्देश्य के अनुरूप परवान नहीं चढ़ पाई, हालांकि वर्तमान में 70 फीसद लोगों के आधार कार्ड बनाने का काम पूरा कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि 13वें वित्त आयोग के तहत राशि का आवंटन किया गया था। ऐसे में प्रदेश सरकार शेष राशि हासिल करने के लिए भारी मशक्कत करनी होगी। कारण यह है कि 13वें वित्त आयोग का समय समाप्त हो चुका है। उधर, सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बीपीएल आबादी आठ करोड़ है। ऐसे में अतिरिक्त राशि की व्यवस्था को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार अतिरिक्त राशि देती है या नहीं!